

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 4 मई 2024 शनिवार

सम्पादकीय

नोट पर वोट....?

केन्द्रीय चुनाव आयोग नकदी जवाब देने का पिछला सारा रिकॉर्ड इस चुनाव में तोड़ देगा, जब की गई नकदी का आंकड़ा देख कर यही लगता है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कुछ समय बाद ही यह आंकड़ा 4,650 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। प्रतिदिन औसतन 100 करोड़ रुपए की बरामदगी में प्रायः सभी दलों के प्रत्याशी शामिल रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक में भाजपा के उम्मीदवार डा. के. सुधाकर से 4.8 करोड़ रुपए नकदी की बरामदगी हुई। पिछली बार 2019 के पूरे चुनाव में जब कुल नकदी 3475 करोड़ रुपए थी। यह पिछले चुनाव के दौरान एकत्र की गई कुल राशि से 34 फीसदी अधिक है। कोई दावे से नहीं कह सकता कि 7 चरणों का मतदान खत्म होने पर यह आंकड़ा कितना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनावी बांड की वैधता पर फैसला देने के ठीक दो महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी चर्चा करते हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा चुनावी बांड योजना को खर कर देने के बाद देश को पूरी तरह से काले धन की ओर घुमने दिया है और ईमानदारी से सोचेंगे तो हर किसी को इसका पछतावा होगा। हैरत की बात है कि इस मुद्दे पर सरकार और कोर्ट दोनों ही पारदर्शिता की बात करते हैं। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पुनर्क संशोधित दूसरी स्कीम लाने की बात करती हैं। उच्चतम न्यायालय की मदद के बिना लेन-देन के इस मामले का ज्ञान देश की जनता के लिए संभव नहीं था। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद ही नोट के बदले वोट का असली खेल शुरू होता है। इस खेल से लंबे समय से भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंच रहा है।

साल 2008 में परमाणु समझौते के बाद वायुपंथी दल ने यू.पी.ए. सरकार को बाहर से समर्थन देना बंद कर दिया था। नतीजतन अविश्वस प्रस्ताव का सामना करने वाली मनमोहन सिंह सरकार पर नोट के बदले वोट का आरोप लगा था। लोकसभा में अशोक अर्गल, फगन सिंह कुलसे और महावीर भगोड़ा जैसे तीन भाजपा सांसद नकदी के बंडल बहा कर सत्ता पक्ष पर खरीद फरोखत का आरोप लगाते हैं। लंदन में साक्ष्य के अभाव के नाम पर इसे दबा दिया गया। यह एक अबूझ पहेली बन कर गई। राज्य विधानसभाओं में खरीद-फरोखत बराबर होती है। इसी वजह से पांच सितारा होटलों में वि.पाकों को नजरबंद करने की परम्परा कायम हुई।

विशवास मत की आड़ में विकसित हुई इस व्यवस्था का अपना महत्व है। कांग्रेस नेता और तेलंगाणा के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को जब राज्य की पुलिस द्वारा 2015 में गिरफ्तार किया गया था तो वह तेंपेदा के सस्पय थे। नौ साल पहले उन्हें वि.पायक एलिवस स्ट्रीफेसन को वोट के लिए 50 लाख रुपए की रिश्तत देते हुए पकड़ा गया था। यह मामला आज भी कोर्ट में लंबित है। सत्ता के निचले पायदान पर स्थिति बहुत गंभीर है। लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले आम नागरिक क्या इस पर किसी से पीछे रहना चाहते हैं? बरामती में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बीच जगजग में नियंत्रण करने वाली जनता में ऐसे लोगों की कमी नहीं, जो खुल कर पैसा लेने की बात स्वीकार रहे हैं।

पार्टी के मुख्यमंत्री ने खुले-आम दिल्लीवासियों से दूसरी सत्ता से पैसे लेकर आम आदमी पार्टी को बोल करने की अपील की। ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता है कि चुनावी बांड योजना के जारी रहने पर नकदी बांटेने का खेल भी खत्म हो गया होता। आधुनिक भारत की राजनीति पर लालच का दुस्तथापन रोग हाव है। सरकार राजनीतिक चंदे को नकदी से बैंकिंग सिस्टम में लाने का काम भी पारदर्शिता समझती है। यदि इसमें सच्चाई नहीं होती तो ई.डी. और सी.बी.आई. के छापों के बाद बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों के साथ भाजपा की साठ-गांठ पर चर्चा नहीं चल रही होगी।

इस एक संकट के साथ भय और भ्रम का मायाजाल पसर है। मतदान की गोपनीयता का कानून इस पर आधारित है। सामाजिक और आध्यक गैर-बराबरी के कारण ऐसा ही होता रहेगा। फिरगियों को पता था कि देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले वीरों का भारत नियम-कानून के दूते ही कमजोर किया जा सकता है। राजनीतिक अंधश्र्वास का तिलिप्सी खेल आंखों के सामने हो कर भी ओझल प्रतीत होता है। इस परिस्थिति में आम जनता के सामने मनोरंजन के साधन बढ़ते रहेंगे और शासन व्यवस्था से जुड़ी बातें गोपनीयता का लबादा ओढ़ती बढ़ेंगी। देवरेम और लोक वधा की भावना आजादी की लड़ाई के प्रगण तत्व माने गए हैं। आजादी के बाद सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में क्या यह भाव कहीं है? राजनीति में धनबल व बाहुबल का खनाद होने लगा है। क्या अब पारदर्शिता की बात पर विधायिका और न्यायपालिका में सहमति कायम होगी? राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता की बात पर सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि कोर्पोरेट योगदान पूरी तरह से व्यावसायिक लेन-देन है। यह बदले में लाभ हासिल करने के इरादे से ही किया जाता है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सी.एस.आर.) के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है।

—अशोक के. मेहता—

भाजपा का चुनावी फोकस हाल के चीन तनाव से हटकर 1962 के संघर्ष के दौरान नेहरू के कार्यों को उजागर करने पर केंद्रित हो गया है। चीन आम तौर पर अब तक चुनावी घोषणापत्रों और प्रचार से गायब रहा है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने हाल ही में अजमेर में एक साहित्यिक उत्सव में चीन को भारत के लिए प्राथमिक खतरा बताया था। एल.एस.सी. पर टकराव को जोड़ना एक अच्छी बात थी क्योंकि इससे यह जमीनी हकीकत सामने आ गई थी जिसे स्वीकार करने में दिल्ली को शर्म आ रही थी। विदेश मंत्री एस.जयशंकर और विशेष रूप से रक्षा सचिव गिखर अस्मने ने बीजिंग की निर्दयी संदर्भ दिया है।

नरवणे ने अपनी किताब 'फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी' में भारत-चीन टकराव के बारे में विस्तार से लिखा है जो उनकी देख-रेख में शुरू हुआ था। यह खुफिया जानकारी की एक गंभीर विलक्षण थी जिसने चीन को उनकी 1966 की दावा रेखा के अनुरूप राष्ट्र के भारतीय पक्ष के लगभग 2000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति दी। नरवणे में टाली जा सकने वाली त्रासदी और 21 दौरी के सैन्य वाहन (21 फरवरी को अंतिम दौर) के बाद भी चीन द्वारा अप्रैल 2020 की यथस्थिति बहाल करने से इन्कार ने भारत को गंभीर संकट में डाल दिया है। 1998 में भारत ने चीन को परमाणु परीक्षण को का कारण बताया, जिससे चीन नाराज हो गया और तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह को 'गॉट खोले' के लिए बीजिंग की यात्रा करनी पड़ी।

जयशंकर ने रायशेना डायलॉग में बोले हुए कहा कि चीन को माईड-गैम खेलने की इजाजत नहीं



बीजिंग में इस बात का गवाह था, तब भी जब हमारी सेना टोलोलांग हाइड्रस, कारगिल पर कब्जा कर रही थी। सिंह को कहना पड़ा कि चीन कोई खतरा नहीं है। बाद में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस ने चीन को नंबर एक खतरा बताया। हालांकि इसे नंबर 1 दुश्मन के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया। इससे एक कुत्तनीतिक हमला खड़ा हो गया क्योंकि चीन किसी भी देश द्वारा खतरे के रूप में देखे जाने या इससे भी बदतर खतरे के प्रति बेहद संवेदनशील है। सरकार चीन पर अपनी अस्थिरता में सावधानी बरत रही है क्योंकि उसे कुत्तनीतिक रूप से पूर्ण विघटन सुनिश्चित करने की उम्मीद है। लेकिन फरवरी 2020 में हाताहत बदल गए।

जयशंकर ने रायशेना डायलॉग में बोले हुए कहा कि चीन को माईड-गैम खेलने की इजाजत नहीं

दी जानी चाहिए जिसका मुकाबला करने के लिए भारत को बेहतर संतुलन हासिल करने के लिए अन्य तरीकों (अमेरिकी मदद) का इस्तेमाल करना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी दिल्ली में इंडस-एक्स फोरम में अस्मने द्वारा अनुप्रायु रूप से बीजिंग को धमकाने वाला कई जाने के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था, "हमें उम्मीद है कि अगर हमें हमारे समर्थन की जरूरत होगी तो हमारा मित्र अमेरिका बाह मौजूद रहेगा।" 1962 के बाद से हमने स्पष्ट रूप से अमेरिकी सैन्य समर्थन नहीं मांगा है। इससे चीन का परेशान होना लगभग है। इससे भी बुरी बात यह है कि किसी भी भारतीय अधिकारी ने कभी भी चीन को बीजिंग नहीं कहा। आश्चर्य की बात है कि चीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

प्रकाशकों द्वारा ओपिनियन स्तंभ लेखों नाइट 29%30 अगस्त 2020 के अंशों

को प्रसारित करने के बाद सरकार ने नरवणे की पुस्तक और उसके अंशों को बाहि नियंत्रण के लिए रोक दिया है, जिसमें युद्ध में सरकार के राजनीतिक नियंत्रण को कमतर बताया गया है और अग्निवीर पर विस्फोटक टिप्पणियां की गई हैं। चुनावी रैलियों के दौरान जहां विदेश मानों पर उनकी बातचीत से स्पष्ट हो गया। नरवणे की किताब और उसके कुछ अंशों के वितरण पर रोक लगाने के बाद, यह किताब कभी भी फलान नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें युद्ध जैसे स्थिति की राजनीतिक दिशा को खारब रोशनी में दिखाया गया है। लेकिन नरवणे को पता होगा कि वह सी.डी.एस. क्यों नहीं बने, जबकि कैलाश की महत्वपूर्ण ऊंचाईय हमेशा के लिए खो गई हैं।

नरवणे अभियान में, किसी भी भाषाया नेता ने अब तक गलतान या

लेने-देने के हमारे संकल्प से अवगत हो

पूर्व एन.एस.ए. (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) शिव शंकर नेनन ने अपने लेखन में कहा है, "हम नहीं जानते कि दक्षिणी छोर (कैलाश हाइड्रस) में क्या हुआ, जैसा कि हम उत्तरी छोर (पेंगंग त्सो झील) के बारे में जानते हैं।" हाल ही में कांग्रेस नेता जयराज रमेश ने स्वायत्त लड़ाख हिल डिवेलमेंट काऊंसिल के सुशुल काऊंसलर कोनचोक स्टैनलिन के एक एक्स पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि राजगला युद्ध स्मारक 1962 को नष्ट कर दिया गया था क्योंकि यह कैलाश हाइड्रस के खाली होने के दौरान चीन के साथ बातचीत के दौरान 'बर्फ जोन' में आता था। भारतीय क्षेत्र में निर्वादा कैलाश हाइड्रस को बर्फ जोन बना दिया गया था, यह एक रहस्योद्घाटन है कि सरकार ने संसद को कभी भी सूचित नहीं किया।

उस महत्वपूर्ण रात को कैलाश हाइड्रस में विकसित ऊष्मधर और शैलिंग बुद्धि से मरी गंभीर परिचालन स्थिति में, सी.सी.एस.आर. एम.डी. एम. द्वारा नरवणे को कोई राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया गया था, जो सिंह के साथ तत्काल आदेश मानने पर उनकी बातचीत से स्पष्ट हो गया। नरवणे की किताब और उसके कुछ अंशों के वितरण पर रोक लगाने के बाद, यह किताब कभी भी फलान नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें युद्ध जैसे स्थिति की राजनीतिक दिशा को खारब रोशनी में दिखाया गया है। लेकिन नरवणे को पता होगा कि वह सी.डी.एस. क्यों नहीं बने, जबकि कैलाश की महत्वपूर्ण ऊंचाईय हमेशा के लिए खो गई हैं।

नरवणे अभियान में, किसी भी भाषाया नेता ने अब तक गलतान या

छात्र आंदोलन और अमेरिकी सख्ती का प्रश्न



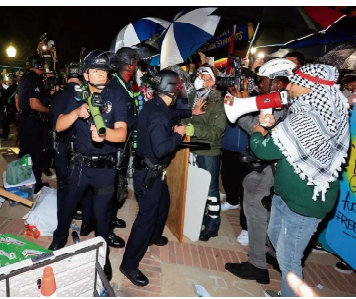
—पुष्परंजन—

अमेरिका में चुनाव तक गजा का सवाल विश्वविद्यालयों में गुंजता रहा। इसकी गुंज फ्रांस के शिक्षा केंद्रों में भी होने लगी है। क्या भारत में इसका वायवस फैलने वाला है? यह सवाल देश के अनेक विचारकों से मिलना बाकी है। पिछले हफ्ते पेरिस के एक शीर्ष विश्वविद्यालयों का 'साइसेज-पो' में अमेरिका की 'देवडोली' फलरलीती समकक प्रदर्शन शुरू हुआ। इमैगुएल मैको इस प्रदर्शन से इतने नाराज हुए कि 'साइसेज-पो' की फंडिंग ही निलंबित कर दी।

'साइसेज-पो' में राष्ट्रपति ट्रिम्पुएल मैको और उनके प्रधानमंत्री गाब्रिएल अडल पड़ाई कर चुके हैं। लेकिन ऐसा फैसला लेते समय मैको ने इसका लिहाज नहीं किया। गजा में जारी युद्ध, फ्रांस के लिए संवेदनशील मुद्दा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप के युद्धियों और प्रवासी मुसलमानों के लिए घर जैसा है, इसलिए दोनों तरफ से टकराव की स्थिति बन रही है।

फ्रांस के दूर वामपंथी एलएफआई (छात्र इंसोआजिड) के सांसदों ने छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। मई दिवस के दिन ज्यों लुई मेलेन्कोले ने रुडिगियरों और मैको सरकार के असहस्यवादी व्यवहार का आलोचना की है। फ्रांसीसी ग्रहणामंत्री गाब्रिएल अडल ने कहा कि वह किसी गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन 'साइसेज-पो' के शैक्षिक माहौल को अवरुद्ध करने वाले अनैच्छिक छात्र, बहुसंख्यकों को अपने विचार थोका रहे थे। ऐसी विचार आरा को हम अरुदातलिक पार से आयातित कह सकते हैं।

लेकिन इस समय जेरे बहस जो बाइडेन है, जिसके चुनाव के समय अमेरिकी विश्वविद्यालयों में जोदार प्रदर्शन हो रहे हैं। 1 मई तक अमेरिका के 30 से अधिक कैम्पसों में हुए प्रदर्शनों में 1400 से अधिक प्रदर्शनकारी



गिरफ्तार किये गये हैं। गजा में नरसंभार रोकने के सवाल पर लगातार हुए प्रदर्शनों को रोकने के पारते, और यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए अमेरिकी कांसस में बुधवार को एक विधेयक पास हुआ।

इसके साथ में 320 सांसद थे, और विरोध में 91 इक्कीस रिपब्लिकन और 70 डेमोक्रेट्स ने इसके खिलाफ मतदान किया था। बहुसंख्यक अमेरिकी जनता युद्धविरोध के पक्ष में है, बावजूद इसको जो बाइडेन की जिद कहिए कि अमेरिका इसासल का समर्थन कर रहा है। इस समय न्यू यार्क स्थित कां तो बिज्या विश्वविद्यालय में तनाव की स्थिति है। बुधवार को संयुक्त राज्य महासभा की बैठक में इज्जालत के राजदूत गिलाल नेताने छान प्रदर्शनकारियों की निंदा की। गिलाल एर्पन ने कहा, हम हमेशा से जानते थे कि हमारा स्कूलों में छिपा है हमें यह अहसास ही नहीं हुआ कि यह सफ़ा गजा के स्कूलों में नहीं है, बल्कि अमेरिका में हाईड्र, कोलंबिया जैसे कुलीन विश्वविद्यालयों भी इनके केंद्र हैं।

बाइड हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है कि छात्रों द्वारा एक शैक्षणिक बन पर कब्जा करना बिल्कुल गलत है। इसे शांतिपूर्ण विधेय हमें कर्तई नहीं कह सकते। डेमोक्रेट जनाल बहस को कोलंबिया विश्वविद्यालय के पास न्यूयार्क स्थित का प्रतिनिधि त्व करते हैं, ने इसे रोकने का आह्वान किया। बॉमन ने एक बयान में कहा, 'कॉलेज पेरिसरों का सैन्यीकरण, पुलिस की व्यापक उपस्थिति और सैकड़ों छात्रों की गिरफ्तारी, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद के बरअकस है। विरोध प्रदर्शनों से

निपटने के तरीके को लेकर कोलंबिया की अध्यक्ष मिनाचे शकीरी ने हिंसा की निंदा की और कहा कि कैम्पस में शैक्षणिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए। कोलंबिया युनिवर्सिटी में जब टैंट गाराफर प्रदर्शनकारी अड गये, और पुलिस ने उसे खपली कराने के लिए जिस तरह से बल प्रयोग किया, उसे कोई भी आमन पदव व्यक्ति सत्ता नहीं सकता।

अमेरिका में प्रदर्शनकारियों को दोनों हाथों को पीछे कर हथकड़ी लगाकर ले जाने वाले विजुअली प्रतीक बन चुके हैं। यह किसी भी लोकतंत्रवादी को रास नहीं आ सकता। वहीं अमेरिका भारत को लोकतंत्र की नीहात देता है। अक्सर, अमेरिका की बंदर और बेहिस पुलिस पर सवाल करने की मनाही है। वर्ष 2005 में पैगामन से वारिशट्टा डीसी के बाल्टीमोर तक मेट्रो के स्फुर को मूला नहीं हू, जब बुरिफा सह एक स्कूली छात्र को पुलिस हथकड़ी लगाकर ले गई। अमेरिका में छोटी-छोटी बातों पर पुलिस द्वारा निर्यात बना देना, पकड़कर पीछे से हथकड़ी लगा देना सामान्य—सी बात है।

भारत में जलन्य आराधिका ममलो वाले अभियुक्तों की हथकड़ी लगाने का कोई आदेश मिलाता है। 80 के दशक में सामाज्य अपराध मानने में हथकड़ी पर रोक लगा दी गई थी। उमर खलालत को हथकड़ी लगा देने के आयेदन को यह करते हुए दिल्ली की अदालत ने टिप्पणी की थी कि उमर कोई गैरतट नहीं है। तो क्या लोकतंत्र का चौधरी बने अमेरिका को भारत से नसीब नहीं की जरूरत है? गजा के दमन चक्र के सवाल पर अमेरिकी कैम्पस कुछ हप्तों से छिटपुट प्रदर्शनों की चपेट में थे।

लेकिन 22 अप्रैल, 2024 को यह प्रदर्शन फैल गया, जब न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय, एमर्सन कॉलेज, मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) और टट्टस विश्वविद्यालय सहित पूरी तट के कई पेरिसरों पर छात्रों ने टेंट लगाकर कब्जा करना शुरू कर दिया। 40 से अधिक कैम्पसों में प्रोटेस्ट कैंप लगा देखकर सरकार के हाथ-पांव कुल बूके थे। प्रदर्शन स्थल पर टेंट गाइ देने से जो बाइडेन प्रशासन की भुलुटि टेल बुकी थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय में तौता समूहों ने पिछले बुधवार को 'टेंट सिटी' स्थापित की। ये समूह है स्टूडेंट फोर जस्टिस इन फलरसिटी (एस्जेबी), जेविश यॉक्स फोर पीस (जेवीपी) और विदीन और लाइफटाइम। छात्रों ने युनिवर्सिटी प्रशासन से अंगीत की थी कि वह उन कर्मचारियों के साथ काम करना बंद करे, जो गजा में युद्ध का समर्थन कर रहे हैं।

25 अप्रैल, 2024 को एमर्सन कॉलेज, दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और बंड पेसास विश्वविद्यालय में बाइडेन सरकार पर गिरफ्तारियां हुईं। प्रदर्शन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में फैल गए। गत 27 अप्रैल को जाकी कारेंडाई के कारण वाशिंगटन डीसी, एरिजोना और इंडियाना विश्वविद्यालयों में लगभग 275 गिरफ्तारियां हुईं। एमपी विश्वविद्यालयों में हिरासत में लिए गए लोगों में कई प्रोफेसर भी शामिल थे। वाशिंगटन विश्वविद्यालय में कर्मचारियों तक को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन यह सब कुछ एकरतफा नहीं था। 28 अप्रैल को एमआईटी विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिलस के यूसीएलए में जावरी विरोध। प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रोटेस्ट के जवाब में कांटर प्रोटेस्ट/ कोन करा रहा था, ये सब?

चूंकि अमेरिका में यह चुनाव है वह है, यहां सबसे पावरफुल इज्जाल समर्थकों लोबी 'अमेरिकन इज्जाल पब्लिक अफेयर्स कमेटी' (एफआईपीसी) जो बाइडेन के समर्थन में मागिल बनाते में लगी थी। उसके प्रयासों पर पानी फिर गया लगता है। एफआईपीसी की बरकर यहूदी अवस्थात जार्ज सरोस खड़े हैं, जो इज्जाल के विरुद्ध प्रदर्शनों के लिए मोटी फंडिंग कर रहे हैं।

—लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

शंकाओं का हो साधान



—डॉ. शशांक द्विवेदी—

कोविड वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर देश-दुनिया में कई तरह के सवाल उठार जा रहे हैं। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एंजेलिका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से लाइफ स्टार्टाले लोग घंटी ऑफिस में एक जगह बैठकर काम करते हैं, जिसके कारण वे सारी सोमरियायों का खारब बड़ जाता है। जरी आवा कान्ही देश तक एक ही जगह बैठे रहते हैं तो शरीर में खून के थक्के जमने की समस्या बड़ जाती है। शरीर में खून के थक्के जमने को 'वेन थ्रोम्बोसिस' की बीमारी कहते हैं।

ब्लड क्लॉटिंग की बीमारी किसी भी व्यक्ति के शरीर में खून के थक्के जमा जाते हैं और ब्लेटवेडस की संस्था फिर जाती है। अप्रैल, 2021 में जेम्सी स्कॉट नाम के शख्स ने यह वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनेने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के भ्रेन में इंटर्नल ब्लडिंग भी हुई। शरीर के मुताबिक, डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्रोजेनिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मई, 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन से एंटीकोअल नहीं घुलता है। हालांकि, इस साल फरवरी में हाईकोर्ट में जना किए दस्तावेजों में कंपनी इस बात से पलट गई। उल्लेखनीय है कि दुनिया संबंधित मामलों को देखते हुए यूके में अब ऑक्सफोर्ड-एस्ट्रोजेन की वैक्सीन इस्तेमाल नहीं की जाती है। हालांकि, कई इंडिपेंडेंट स्टडीज ने इस वैक्सीन को महामारी से निपटने में बेहद कारगर बताया गया। वहीं, साइड इफेक्ट्स के मामलों की वजह से इस वैक्सीन के खिलाफ खड़ा शुरू की गई और कार्मोई कर्माई हुई। कोरोना से बचाने में कोविड वैक्सीन को काफी मददगार माना

कैलाश की पहाड़ियों का उल्लेख नहीं किया है, जो चीन के खिलाफ बल के वीरतापूर्ण उपयोग का उदाहरण थे क्योंकि इससे कई खतरे पैदा हो सकते थे। नरवणे को मानना से बाहर रखते हुए, विश्व 2000 वर्ग कि.मी. भूमि के साथ-साथ 65 गरीबी बिडुओं में से 26 को खोने के लिए सरकार पर हमला कर रहा है। 12 अप्रैल को पुणे में प्रचार करते हुए और मीडिया से बात करते हुए जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि 'चीन द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया'। इसने हमारी किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया लेकिन स्थिति संवेदनशील, प्रतियस्फी और चुनौतीपूर्ण है।' प्रधानमंत्री, गुमनामी और शरामंत्री सभी ने क्षेत्र के नुकसान से इन्कार किया है।

यू.जी.वी.के के साथ अपने साक्षात्कारों में चीन पर एक साल के जवाब में, पी.एम. मोदी का संक्षेप उत्तर था, 'बीजिंग के साथ नई दिल्ली के संबंध महत्वपूर्ण हैं और सीमा पर लंबे समय से चली आ रही स्थिति पर तत्काल गौर किया जाना चाहिए ताकि सीमाओं पर शांति और अमन-चौन बहाल किया जा सके।' चीनियों ने बयान का स्वागत करते हुए कहा कि मजबूत और स्थिर संकेत अंका हित में हैं। भारत की मांग के अनुसार एल.एस.सी. की अपील 2020 से पहले की स्थिति जाना चाहिए नहीं करेगा। किसी समझौते के फलाने की कसबत करण कडिन है। नतीजतन, चीन शब्द भाषाया के चुनावी विमर्श से लगभग गायब है। बातों को बली सतुवाई से 1962 में नेहरू की मूर्खताओं की ओर मोड़ दिया गया। लेकिन नरवणे प्रशंसा के पात्र हैं।

(लेखक एक सेवानिवृत्त मेजर जनरल हैं। यह उनके निजी विचार

की सूचना पर वृजमनगंज के पुलिस कमिश्नी भौ पड़स शान्ति व्यवस्था बनाके के साथ डेलर के पीछिया के नाने के मजदूर के शहीद को बाहर निकाल कच्छे में लिए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वृजमनगंज थाना के प्रभारी निरीक्षक शिव सुन्दर तिलगानी ने बताया कि डेलर को गिरफ्त में ले लिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

